भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2176
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी अवसंरचना

2176. **एडवोकेट प्रिया सरोज:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पोषण अभियान और वन स्टॉप सेंटर जैसी प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत निधि आवंटन/वास्तविक व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) निधि के उपयोग का, विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए, जौनपुर सहित जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान कोई निधि अप्रयुक्त रही और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त जिले में बच्चों (0-6 वर्ष) और गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण दर का ब्यौरा क्या है;

(ङ) विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों में कितने मामले सूचित हुए हैं; और

(च) क्या दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी अवसंरचना का विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): विगत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों सहित उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को जारी

और उपयोग की गई निधि का विवरण **संलग्न** है। मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत निधि के उपयोग का जिला-वार विवरण नहीं रखा जाता है।

(ग): कम उपयोग के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में एकल नोडल एजेंसी/एसएनए स्पर्श (एसपीएआरएसएच) की न्यूनतम शर्तों को पूरा न करना, मानव बल की कम नियुक्ति जिसके कारण बचत, निर्माण गतिविधियों के पूरा होने में देरी और उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के निपटान में देरी शामिल है।

(घ) से (च): 30 जून 2025 तक जौनपुर जिले (उत्तर प्रदेश) में बच्चों (0-6 वर्ष) और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण दर का विवरण:

पोषण ट्रैकर के अनुसार कुपोषण संबंधी आंकड़े (0-6 वर्ष)		
क्रं.सं.	**श्रेणी**	**प्रतिशतता (%)**
1.	ठिगनापन	53.98%
2.	कम वजन	22.64%
3.	दुर्बलता (0-5 वर्ष)*	5.63%

*0-5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए पोषण ट्रैकर पर कुपोषण के आंकड़े रखे जाते हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए पोषण ट्रैकर पर अलग से कुपोषण के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनमन मिशन का उद्देश्य 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का लक्षित विकास करना है। यह मिशन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण पहलों पर केंद्रित है। अब तक, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जनमन के तहत 1 आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 01.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2176 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को जारी/उपयोग की गई निधि का विवरण **(करोड़ रुपए)**

क्रं.सं.	मिशन	योजना	वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25	
			जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि
1.	मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0	आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना	2721.87	2622.64	2668.69	2510.27	2694.62	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यय का प्रमाण पत्र/विवरण देय नहीं है।
2.	मिशन वात्सल्य (पूर्व में एकीकृत बाल संरक्षण योजना)		66.05	49.40	103.57	76.06	92.05	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यय का प्रमाण पत्र/विवरण देय नहीं है।
3.	मिशन शक्ति – संबल	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	0.00	8.11	20.93	12.02	0.00	16.88
		वन स्टॉप सेंटर	3.47	7.29	18.13	20.43	18.01	20.53

		वीमेन हेल्प लाइन	0.17	0.00	0.96	0.77	0.76	0.85
4.	मिशन शक्ति – सामर्थ्य	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	500.68	384.53	0.00	74.79	0	82.55
		शक्ति सदन (पूर्व में स्वाधार गृह और उज्ज्वला)	1.58	1.58	0.00	0.00	7.84	1.35
		सखी निवास (पूर्व में कामकाजी महिला छात्रावास)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
		महिला सशक्तीकरण के लिए हब	5.90	-	0.00	-	7.80	-

*****